year to preside over the meetings of the Corporation during his absence in order of the name in the panel.

(3) The meeting under sub-section (1) shall be called and presided over by the Collector.

(4) The term of the Speaker shall be coterminous with the term of the Corporation.]

[1][18-A. Powers and functions of the Speaker -- (1) Subject to the provisions of the Act, the speaker shall have the following powers and functions :-

(i) to preside over the meetings of the Corporation and send the copy of proceeding to the Commissioner within seven days form the date of meeting;

(ii) to fix the date of the meeting of the Corporation with the consent of the Mayor and arrange to send the notice thereof alongwith the Agenda as approved by the Mayor, and

(iii) to have administrative control over the officers and servants of his office including the Corporation Secretary.

(2) The Speaker shall have power to call the execution report from the Commissioner, on the decisions taken in the meeting of the Corporation, and may take steps to include in the agenda of the next meeting of the

प्रतिवर्ष दो निर्वाचित पार्षदों की एक नामावली घोषित करेगा जिसमें नामावली में दिए गए क्रम में नाम होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन सम्मिलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष की पदावधि, निगम की पदावधि की सह-विस्तारी होगी।]

[1][18-क. अध्यक्ष (स्पीकर) की शक्तियाँ तथा कृत्य -- (1) इस अधिनियम के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य होंगे :-

(एक) निगम के सम्मिलन की अध्यक्षता करना तथा सम्मिलन की तारीख से सात दिन के भीतर आयुक्त को कार्यवाही की प्रतिलिपि भेजना;

(दो) महापौर की सहमति से निगम के सम्मिलन की तारीख नियत करना तथा उसकी सूचना उस कामकाज की सूची (एजेण्डा) के साथ जो कि महापौर द्वारा अनुमोदित की गई है, महापौर को भिजवाने की व्यवस्था करना; और

(तीन) अपने कार्यालय के अधिकारियों तथा सेवकों जिसमें निगम का सचिव भी सम्मिलित है, पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना।

(2) अध्यक्ष को नगरपालिक निगम के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चयों पर आयुक्त से निष्पादन रिपोर्ट मंगवाने की शक्ति होगी तथा वह ऐसे मामलों को जहाँ निष्पादन तीन माह से परे लम्बित रहा हो, निगम के आगामी सम्मिलन के कामकाज की

---

1. Ins. by M.P. Act No. 29 of 2003, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same Section 18-A inserted in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 03-01-2005. **So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**

Corporation such matters in which execution has been delayed beyond three months.]

सूची (एजेण्डा) में सम्मिलित करने के लिए कदम उठा सकेगा।]

19. Removal of Councillors -- (1) The [1][Divisional Commissioner] may at any time, remove any [2][elected] [3][..........] councillor --

(a) if his continuance as a councillor is not, in the opinion of the [1][Divisional Commissioner], desirable in the interest of the public or the corporation; or

[4][(a-1) if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved, or]

(b) if the Corporation has, by a resolution supported by at least two third of the total number of councillors; recommended that a councillor is not fit to continue as a councillor on account of misconduct in the discharge of his duties or disgraceful conduct and should therefore be removed.

(2) The [1][Divisional Commissioner] may, while ordering the removal under [5][sub-section (3) of Section 23] or this

19. पार्षदों का हटाया जाना -- (1) [1][संभागीय आयुक्त] किसी भी [2][निर्वाचित] [3][..........] किए गए पार्षद को किसी भी समय हटा सकेगा --

(अ) यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना [1][संभागीय आयुक्त] के मत में सार्वजनिक या निगम के हित में वांछनीय न हो;

[4][(अ-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, या]

(आ) यदि निगम ने ऐसे ठहराव द्वारा जो पार्षदों की सम्पूर्ण संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो, या सिफारिश की हो कि ऐसा पार्षद अपने कर्तव्यों के सम्पादन में कदाचरण या अशोभनीय आचरण का दोषी होने के कारण पार्षद होने के योग्य नहीं है और इसलिए उसे हटा दिया जाना चाहिए।

(2) [1][संभागीय आयुक्त] [5][धारा 23 की उपधारा (3)] या इस धारा के अधीन हटाने की आज्ञा देते समय, यह आज्ञा भी दे सकेगा कि ऐसा पार्षद

1. Subs. by M.P. Act No. 18 of 1997, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997. In State of C.G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C.G. Act No. 6 of 2003, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214(2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" **subs. by Sec. 3 of C.G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words are applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**
2. Subs. by M.P. Act No. 13 of 1961.
3. Omitted by M.P. Act No. 18 of 1997, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.
4. Ins. in State of M.P. by M.P. Act No. 29 of 2003, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 25-8-2003 and in State of C.G. **by Sec. 3 of C.G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012), published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). So, now clause (a-1) is applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**
5. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1998, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.

CHAPTER IV
MUNICIPAL OFFICERS AND SERVANTS

The Commissioner

54. Appointment and removal of Commissioner -- (1) The Commissioner for the Corporation shall be appointed by the Government for a renewable period not exceeding five years.

(2) He shall be forthwith removed from office if at a meeting of the Corporation not less than three-fourths of the total number of [1][elected councillors] vote in favour of a proposition in this behalf; and he may be removed by the Government at any time if it appears to the Government that he is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of any misconduct or neglect which renders his removal expedient :

Provided that when the Commissioner holds a lien on any post under the Government, he may be recalled at any time by the Government. [2][.........]

55. Power of Commissioner -- The Commissioner shall be the principal executive officer of the Corporation and all other officers and servants of the Corporation except the servants and officers of the Corporation office shall be subordinate to him. He shall have the right to speak at, and otherwise take part in any meeting of the Corporation or any Committee thereof, but shall not be entitled to vote or to move any proposition.

56. Salary of Commissioner -- (1) The Commissioner shall receive such

चौथा अध्याय
नगरपालिक पदाधिकारी तथा सेवक

आयुक्त

54. आयुक्त की नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना -- (1) निगम के लिए आयुक्त की नियुक्ति ऐसे नवीनीकरण योग्य काल के लिए जो 5 वर्ष से अधिक न हो, शासन द्वारा की जाएगी।

(2) वह अपने पद से तुरन्त हटा दिया जाएगा, यदि इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में निगम के किसी सम्मिलन में [1][निर्वाचित पार्षदों] की कुल संख्या के इतने सदस्यों द्वारा मत दिया जाए, जो तीन-चौथाई से कम न हो, और वह शासन द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा, यदि शासन को यह प्रतीत हो कि वह अपने पद के कर्तव्यों का सम्पादन करने में असमर्थ है या वह किसी ऐसे दुराचरण या प्रमाद का दोषी रहा है, जिससे उसका हटाया जाना उचित ठहरता हो :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब आयुक्त शासन के अधीन किसी पद का स्वत्वभार रखता हो तो उसे [2][.........] किसी भी समय शासन द्वारा [2][.........] वापस बुलाया जा सकेगा।

55. आयुक्त की शक्ति -- आयुक्त निगम का मुख्य कार्यपालिक पदाधिकारी होगा और निगम कार्यालय के सेवक तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त निगम के समस्त अन्य पदाधिकारी तथा सेवक उसके अधीन होंगे। उसे निगम के या उसकी किसी समिति के सम्मिलन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का स्वत्व प्राप्त होगा, किन्तु वह मत देने का या कोई प्रस्ताव रखने का स्वत्वाधिकारी नहीं होगा।

56. आयुक्त का वेतन -- (1) आयुक्त ऐसा मासिक वेतन तथा ऐसे मासिक भत्ते

1. Substituted by M.P. Act No. 12 of 1995.
2. Omitted by Section 3 (2) of M.P. Act No. 13 of 1961.

monthly salary and such monthly allowances as the Government may, from time to time determine.

(2) [1][Subject to the provisions of sub-section (1), the condition of service] of a person appointed as a Commissioner, who holds a lien on a post under the Government during the tenure of his aforesaid appointment, shall be such as may be laid down by the Government and in any other case they shall be such as may laid down by [2][byelaws] framed by the Corporation.

57. Grant of leave of absence to Commissioner -- (1) The Government may with the previous consent of the Corporation grant leave of absence to the Commissioner.

(2) During any absence on leave of the Commissioner the Government shall appoint a person to act as the Commissioner.

(3) Every person so appointed shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Commissioner by this Act or by any other enactment for the time being in force, and shall be subject to the same liabilities, restrictions and conditions to which the Commissioner is liable and shall receive such monthly salary and allowances, as the Government may determine.

प्राप्त करेगा जिन्हें शासन समय-समय पर निरूपित करे।

(2) आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के, जो शासन के अधीन किसी पद पर स्वत्वभार रखता हो, अपनी पूर्वोक्त नियुक्ति के कार्यकाल में [1][उप-धारा (1) के आदेशों के पालन के अधीन, सेवा के प्रतिबंध] वही होंगे, जो शासन द्वारा नियत किए जावें, और किसी अन्य दशा में वे ऐसे होंगे जैसे कि निगम द्वारा बनाई गई [2][उपविधियों] द्वारा किए जावें।

57. आयुक्त को अनुपस्थित रहने की अनुमति का प्रदान किया जाना -- (1) शासन निगम की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त को अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(2) आयुक्त के अवकाश पर अनुपस्थित होने के समय शासन आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा या तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा, आयुक्त को प्रदान की गई शक्तियाँ प्रयोग में लाएगा और उस पर आरोपित कर्तव्यों का सम्पादन करेगा और वह उन्हीं दायित्वों, आयन्त्रणों तथा प्रतिबंधों के पालन के अधीन होगा, जिनके अधीन आयुक्त दायी है और वह ऐसा मासिक वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा जैसा कि शासन निरूपित करे।

टिप्पणी

नगर निगम के किसी प्रभारी कमिश्नर द्वारा अनुशासनिक शक्ति प्रयोग में नहीं लाई जा सकती -- कमिश्नर का साधारण प्रभार संभालने वाला सीटी इंजीनियर धारा 58 (1) के अधीन शक्ति को प्रयोग में नहीं ला सकता। **गोविंद कुमार सेन बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (1) एम.पी.एल.जे. 517।**

[3][**58. Appointment and conditions of Service of Corporation Officers and servants** -- (1) Subject to

[3][**58. निगम अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें** -- (1) निगम के अधिकारियों तथा सेवकों के स्थापन (सेट अप),

1. Subs. by Section 3 (2) of M.P. Act No. 13 of 1961.
2. Subs. by M.P. Act, No. 13 of 1961.
3. Subs. by M.P. Act No. 12 of 1995, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 1-5-1995.

the rules made by the State Government in respect of the Set-up, Strength, Recruitment, Appointment, Pay-Scales, Allowances and other conditions of service of officers and servants of the Corporation, the corporation shall appoint such officers and servants as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Corporation :

Provided that --

(i) the power of appointing any person on a municipal post which carries a maximum scale of pay as the State Government may, from time to time, by an order in writing specify, shall vest in the [1][Mayor-in-Council] or the Commissioner;

(ii) any appointment made within his power by the Commissioner shall be reported for information to the [1][Mayor-in-Council].

(iii) every appointment to be made by the [1][Mayor-in-Council] shall be subject to the prior confirmation of the State Government. The decision of the State Government in this behalf shall be final.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in emergent situations, the [1][Mayor-in-Council] may make adhoc appointments for a period not exceeding six months, with prior permission of the State Government.]

[2][(2a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), the Mayor-in-Council may, with prior permission of the State Government, appoint on contract, specialist officers

उनकी संख्या, भरती, नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, निगम ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करेगा जैसा कि निगम के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो :

परन्तु --

(एक) किसी ऐसे नगरपालिक पद पर जिसका कि अधिकतम वेतनमान ऐसा हो, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति [1][मेयर-इन-कौंसिल] या आयुक्त में निहित होगी;

(दो) आयुक्त द्वारा अपनी शक्ति के भीतर की गई किसी नियुक्ति के संबंध में रिपोर्ट [1][मेयर-इन-कौंसिल] को जानकारी के लिए दी जाएगी।

(तीन) [1][मेयर-इन-कौंसिल] द्वारा की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति, राज्य सरकार के पूर्व पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए होगी। इस संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं आपात स्थितियों में [1][मेयर-इन-कौंसिल] राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से छह मास से अनधिक कालावधि के लिए तदर्थ नियुक्तियाँ कर सकेगी।]

[2][(2-क) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मेयर-इन-काउन्सिल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, प्रबन्धन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, अभियान्त्रिकी और योजना

1. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1998, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.
2. Ins. by M.P. Act No. 16 of 2007, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478(3). **Applicable only in Madhya Pradesh.**

and servants in the field of management, accounts, information technology, engineering and planning for specified periods and the manner and terms and conditions of appointment of such specialists officers and servants on contract, shall be such as may be prescribed by the State Government.]

(3) The State Government may depute to any post under the corporation carrying maximum scale of pay [1][as the State Government may, from time to time, by an order in writing specify] such servants of the State Government as it may consider necessary [2][:]

[3][Provided that in case of technical posts, the State Government may depute servants of any Town and Country Development Authority and Government undertaking to any Municipal Corporation for a period not exceeding one year.]

(4) The terms and conditions of deputation of [4][servants of the State Government, Town and Country Development Authority or Government undertaking] [5][servants of the State Government] including disciplinary control shall be such as may be prescribed.

[6][(5) Notwithstanding anything contained in this Act or any rules or byelaws made thereunder, the State Government may, subject to the

के क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारियों और सेवकों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे विशेषज्ञ अधिकारियों और सेवकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।]

(3) राज्य सरकार, निगम के अधीन के किसी भी ऐसे पद पर, जिसका अधिकतम वेतनमान [1][जैसा कि राज्य सरकार, समय समय पर, लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे], राज्य सरकार के ऐसे सेवकों को, जिन्हें कि वह आवश्यक समझे, प्रतिनियुक्त कर सकेगी [2][:]

[3][परन्तु राज्य सरकार तकनीकी पदों की दशा में किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी और सरकारी उपक्रम के सेवकों को किसी नगरपालिक निगम में एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगी।]

(4) [4][राज्य सरकार, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी या सरकारी उपक्रम के सेवक] [5][राज्य सरकार के सेवकों] की प्रतिनियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें, जिनके अंतर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी आता है, ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाएँ।

[6][(5) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार [7][किसी नगरपालिक निगम के किसी अधिकारी या सेवक का]

1. Subs. by M.P. Act No. 7 of 1988.
2. Subs. by M.P. Act No. 2 of 2009 for full stop, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 10-2-2009 at pages 99-100(1). **Applicable only in Madhya Pradesh.**
3. Ins. by M.P. Act No. 2 of 2009, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 10-2-2009 at pages 99-100(1). **Applicable only in Madhya Pradesh.**
4. Subs. by M.P. Act No. 2 of 2009 for the words "servants of the State Government", published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 10-2-2009 at pages 99-100(1). **Applicable only in Madhya Pradesh.**
5. **Applicable only in Chhattisgarh.**
6. Substituted by M.P. Act No. 5 of 1982.
7. Subs. by M.P. Act No. 7 of 1988.

conditions specified in sub-section (6), transfer on deputation [1][any officer or servant of a Municipal Corporation] to any other Municipal Corporation and it shall not be necessary for the State Government to consult either the Corporation or the Officer or Servant concerned before passing an order of transfer on deputation under this sub-section.

(6) The officer or servant transferred under sub-section (5) shall --

(a) have his lien on the post held in the parent Corporation;

(b) not be put to disadvantageous position in respect of pay and allowances which he would have been entitled to had he continued in the parent Corporation;

(c) be entitled to deputation allowance at such rate as the State Government may by general order specify, and

(d) be governed by such other terms and conditions including disciplinary control as the State Government may, by general or special order, specify.]

[2][**Explanation** -- For the purpose of sub-sections (3) and (4) :-

(i) **"Town and Country Development Authority"** means the Town and Country Development Authority constituted under Section 38 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किसी अन्य नगरपालिक निगम को ऐसी शर्तों के साथ कर सकेगी, जो उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट हैं, और राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने के पूर्व वह या तो संबंधित निगमों से अथवा संबंधित अधिकारी या सेवक से परामर्श करे।

(6) उपधारा (5) के अधीन स्थानांतरित किया गया अधिकारी या सेवक --

(क) मूल निगम में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा;

(ख) उन वेतन और भत्तों की दृष्टि से, जिनका कि वह मूल निगम में उसके बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा;

(ग) प्रतिनियुक्ति भत्ता ऐसी दर से पाने का हकदार होगा जो राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; और

(घ) अनुशासनिक नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए, ऐसे अन्य निबंधनों तथा शर्तों द्वारा शासित होगा जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]

[2][**स्पष्टीकरण** -- उपधारा (3) और (4) के प्रयोजन के लिये :-

(एक) **"नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 38 के अधीन गठित कोई नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी;

---

1. Subs. by M.P. Act No. 7 of 1988.
2. Added by M.P. Act No. 2 of 2009, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 10-2-2009 at pages 99-100(1). **Applicable only in Madhya Pradesh.**

(2) The [1][Divisional Commissioner], after satisfying himself and verifying that the three-fourth of the Councillors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(2) [1][संभागीय आयुक्त] अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

(3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.]

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा।]

[2][**25. Powers and functions of Mayor** -- (1) The Mayor, shall --

(a) have administrative control over the officers and servants of his office including the office of the [3][Mayor-in-Council] and Appeal Committee;

(b) exercise such powers and perform such functions as described in the Act or the Rules made thereunder.

(2) The Mayor or in his absence [4][such member of the Mayor-in-Council,

[2][**25. महापौर की शक्तियाँ तथा कृत्य** -- (1) महापौर --

(क) अपने कार्यालय के जिसमें [3][मेयर-इन-कौंसिल] तथा अपील समिति का कार्यालय सम्मिलित है, अधिकारियों तथा सेवको पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा।

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

(2) महापौर या उसकी अनुपस्थिति में [4][मेयर-इन-काउंसिल का ऐसा सदस्य जो महापौर

1. In State of C.G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C.G. Act No. 6 of 2003, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214(2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" **subs. by Sec. 5 of C.G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words applicable in M.P. as well as in C.G.**
2. Subs. by M.P. Act No. 18 of 1997, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.
3. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1998, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-9-1998.
4. In State of M.P. subs. by M.P. Act No. 29 of 2003 for the words "the speaker", published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same amendment in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 03-01-2005. **So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**

as may be appointed by the Mayor] in case of epidemic, natural or unforeseen calamity may direct the execution or stoppage of any work or any act, the immediate execution or stoppage of which is necessary for the purpose of this Act :

Provided that --

(a) he shall not act under this sub-section in contravention of any order of the State Government or Corporation or [1][Mayor-in-Council] prohibiting the execution or stoppage of any particular work or act; and

(b) he shall report the action taken under this sub-section and the reasons therefor, to the Corporation at its next meeting and if the Corporation does not confirm the action of the Mayor or [2][such member of the Mayor-in-Council, as may be appointed by the Mayor] as the case may be, the matter shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final, but the State Government before passing any order, which may affect any person a reasonable opportunity of being heard shall be given to such person.]

द्वारा नियुक्त किया जाए], महामारी, नैसर्गिक या अकल्पित विपत्ति की दशा में, किसी भी ऐसे कार्य या किसी भी कृत्य के निष्पादन या रोके जाने के संबंध में निदेश दे सकेगा जिसका तत्काल निष्पादन या रोका जाना इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक है :

परन्तु --

(क) यह राज्य सरकार या निगम या [1][मेयर-इन-कौंसिल] के किसी ऐसे आदेश के, जो किसी विशेष कार्य या कृत्य के निष्पादन को या रोके जाने को प्रतिषिद्ध करता है, उल्लंघन में इस उपधारा के अधीन कोई कार्य नहीं करेगा, और

(ख) वह इस उपधारा के अधीन की गई कार्यवाही तथा उसके कारणों की, निगम को उसके आगामी सम्मिलन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और यदि निगम यथास्थिति महापौर या [2][मेयर-इन-कांउसिल का ऐसा सदस्य जो महापौर द्वारा नियुक्त किया जाए] की कार्रवाई की पुष्टि न करे तो वह विषय राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा, किन्तु राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश, जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करे, पारित करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।]

1. Subs. by M.P. Act No. 20 of 1998, published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-9-1998.
2. Subs. by M.P. Act No. 29 of 2003 for the words "the speaker", published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same amendment in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 03-01-2005. **So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**

[1][25-A. Duties of the Councillors -- Subject to the provisions of the Act, every Councillor shall have the following duties :-

(i) to be present and take part in the meetings of the Corporation and on requirement give vote in his discretion in favour or against, on the matters included in the agenda;

(ii) to draw the attention of the Commissioner or the head of the departments concerned, towards any loss to the Corporation property or any shortcomings in any scheme or service or any work being executed by the Corporation.]

[1][25-क. पार्षदों के कर्तव्य -- अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक पार्षद के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(एक) निगम के सम्मिलन में उपस्थित होना तथा उसमें भाग लेना तथा आवश्यकता होने पर एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर स्वविवेकानुसार पक्ष या विपक्ष में मत देना।

(दो) आयुक्त का या संबंधित विभागाध्यक्ष का ध्यान निगम की सम्पत्ति की किसी हानि या निगम की किसी योजना या सेवा में किसी कमी या निगम द्वारा निष्पादित किए जा रहे किसी कार्य की ओर आकर्षित करना।]

SECTION 25-A APPLICABLE IN CHHATTISGARH ONLY

[2][25-A. Duties of the Councillors -- Subject to provisions of the Act, every Councillor shall have the following duties :-

(i) to be present and take part in the meetings of the Corporation and on requirement cast vote;

(ii) to draw the attention of the Mayor or Commissioner towards any loss to the Corporation property or any

केवल छत्तीसगढ़ में लागू धारा 25-क

[2][25-क. पार्षदों के कर्त्तव्य -- अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक पार्षद के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

(एक) निगम के सम्मिलन में उपस्थित होना तथा उसमें भाग लेना तथा आवश्यकता होने पर मत देना।

(दो) महापौर या आयुक्त का ध्यान निगम की सम्पत्ति की किसी हानि या निगम के किसी योजना या सेवा में किसी कमी या निगम द्वारा निष्पादित किए

1. Ins. by M.P. Act No. 29 of 2003, published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. **Applicable only in Madhya Pradesh.**
2. Ins. by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 03-01-2005. **Applicable only in Chhattisgarh.**